

बार-बार पश्चिम एशिया में अपने सैन्य ठिकानों पर “पिन-पाइन्ट” बमबारी से अमेरिका खीजा

अपने यूरोपीय “मित्रों” पर ट्रंप ने खीज निकाली और उन्हें चेतावनी दी या तो वे लोग इस युद्ध में सीधे (डॉयरेक्ट) जुड़े वरना.

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 मार्च। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बढ़ते ईरानी हमलों के सामने खुद को लगातार असहाय महसूस करते हुए, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूरोपीय देशों से ईरान के खिलाफ अभियानों में सीधे शामिल होने का आग्रह किया।

ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों से कहा कि वे होमरुज से अपना तेल ख़ुद जाकर लें। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका उन्हें पहले की तरह मदद नहीं करेगा। इसके विकल्प के तौर पर, उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपनी तेल ज़रूरतें अमेरिका से पूरी करें, जहाँ पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

इटली ने ईरान में लड़ाकू अभियानों के लिए जा रहे अमेरिकी विमानों को अपने सैगोनेला एयरबेस पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह अनुमति देने से उस समय इनकार किया गया, जब कुछ अमेरिकी विमान अपने

■ ट्रंप ने कहा, यूरोपीय देश अपना “ऑयल” स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते लाने की व्यवस्था खुद करें, अमेरिका इस मामले में उनकी मदद के लिए आयेगा, जबकि यूरोपीय देशों ने भी खाड़ी युद्ध में अमेरिका की मदद नहीं की है या वे लोग अमेरिका से “ऑयल” खरीद सकते हैं। अमेरिका के पास बहुत “ऑयल” है।

■ ट्रंप की यूरोपीय देशों से खीज के कई कारण हैं। उदाहरण के लिए इटली ने खाड़ी युद्ध में बमबारी कर लौट रहे अमेरिकी लड़ाकू विमानों को इटली की भूमि पर “लैंड” करने की इजाज़त नहीं दी, हालांकि युद्ध से पहले से ही इटली व अमेरिका के बीच इस बारे में पुराना अनुबंध व समझौता है।

■ ट्रंप इस बात से भी परेशान हैं कि कोई न कोई ईरान की मदद कर रहा है, अमेरिकी सेना के ठिकानों व अन्य सैन्य गतिविधियों की जानकारी ईरान तक पहुँच रही है, जिससे इतनी “पिन-पाइन्ट” बमबारी हो रही है।

■ अमेरिका के युद्ध संबंधी मामलों के मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन की प्रैस बीफिंग में गुस्से भरे शब्दों में कहा, अमेरिका को पूरी जानकारी है, रूस व चीन की इस युद्ध में क्या भूमिका है।

घरेलू अड्डों से उड़ान भरकर ईरान क्षेत्र की ओर जा रहे थे। इटली ने यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार किया कि संसद से परामर्श के लिए पर्याप्त समय

नहीं था। यह एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि पहले से मौजूद समझौते के तहत, अमेरिकी विमानों को परिचालन क्षेत्रों

की ओर जाते समय इटली में उतरने की अनुमति थी। लेकिन इस बार इनकार के लिए कुछ विशेष कारण बताए गए। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया गांधी स्वस्थ, गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिली

नई दिल्ली, 31 मार्च। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को मंगलवार को सर गंगा राम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें 24 मार्च को बुखार होने के बाद सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोनिया गांधी अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। डॉक्टरों के अनुसार वे एक सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दी गईं।

सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार

■ गत 24 मार्च की रात को बुखार के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सोनिया गांधी को 24 मार्च की रात 10:22 बजे बुखार के चलते सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉ. डीएस राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु की देखरेख में उन्हें एक सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स से इलाज दिया गया और उन्होंने इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दी। अब वे ठीक हो चुकी हैं और आज सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, ताकि घर पर उनका आगे का इलाज और फॉलो-अप हो सके।

‘अमेरिका व्यर्थ ही ऐसे युद्ध में लिप्त हुआ है, जो वो कभी जीत ही नहीं सकता’

अमेरिका के टॉप इकोनॉमिस्ट जैफरी सैक्स के खाड़ी युद्ध के विचार बड़े चौंकाने वाले, पर सटीक हैं

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 मार्च। शीघ्र अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स का पश्चिम एशिया संघर्ष पर हस्तक्षेप अपनी भाषा के कारण नहीं, बल्कि अपने आरोपों की व्यापकता के कारण अधिक उल्लेखनीय है। यह भू-राजनीति, अमेरिकी शक्ति और स्वयं राज्य सत्ता के बदलते स्वरूप तक को कठघरे में खड़ा करता है।

वर्तमान संकट को “दुनिया भर के “लूजर्स” (पराजितों) का युद्ध” बताते हुए, सैक्स मूलतः यह तर्क दे रहे हैं कि इस उभरते टकराव में कोई रणनीतिक विजेता नहीं है, सिर्फ दीर्घकालिक नुकसान के अलग-अलग स्तर हैं। उनका यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय संघर्षों को शून्य-योग (जीरो-सम) प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने की पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। इसके बजाय, वे इसके कई परिणाम देखते हैं, जैसे आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का लगातार क्षरण आदि। उनके अनुसार, जो देश सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हैं,

■ जैफरी सैक्स यह भी कहते हैं कि सबसे बड़ी विवाद की बात है, जिस तरह से “टैक बिलिनियर” (टैकनोलॉजी उद्योगों के अरबपति) मालिक, सरकार के प्रशासन पर भावी हो रहे हैं।

■ जैफरी सैक्स ने हाल ही में प्र.मंत्री मोदी व राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हो रही टेलीफोनिक बातचीत में एलन मस्क के भागीदार होने की भी आलोचना की।

■ उन्होंने कहा, इस अपवित्र दोस्ती में, “जवाबदेही” (एकाउन्टेबिलिटी) और प्रजातंत्रिय वैधानिकता की बलि चढ़ती है।

जैसे भारत, वे भी तेल की ऊँची कीमतों, बाधित व्यापार मार्गों और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण नुकसान उठाएंगे।

सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों के लिए उनकी चेतावनी इसी व्यापक आकलन पर आधारित है। इन देशों ने पिछले दशक में खुद को स्थिरता, निवेश और तेल के बाद के आर्थिक परिवर्तन के केन्द्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, और ऐसे में एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में प्रवेश करना

उनके लिए अत्यंत आत्म-विनाशकारी होगा। सैक्स द्वारा इस्तेमाल किया गया “तेज विनाश” शब्द तत्काल सैन्य हार की भविष्यवाणी से अधिक एक प्रणालीगत विघटन की चेतावनी है, जहाँ वितीय बाजार खत्म हो सकते हैं, बुनियादी ढाँचा निशाना बन सकता है और वर्षों में बनाए गए वैश्विक साझेदारी संबंध रतों-रात कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन सैक्स यहाँ नहीं रुकते, उन्होंने सबसे तीखी आलोचना का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाँच साल के अंतराल के बाद पहला बिज़नेस डैलिगेशन चीन दौरे पर

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल 29 मार्च से 4 अप्रैल तक चीन के दौरे पर है

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 मार्च। देश के उत्तरी हिमालयी पड़ोसी चीन के साथ संबंधों को सहज बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हुए, भारतीय वाणिज्य मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों चीन की यात्रा पर है, जहाँ वह चीन के अपने समकक्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर रहा है। पिछले पाँच वर्षों के विराम के बाद यह इस तरह की पहली यात्रा है।

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) का एक प्रतिनिधिमंडल 29 मार्च से 4 अप्रैल तक शंघाई और चीन के जियांग्सू प्रांत

■ भारत और चीन के संबंध पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य टकराव के बाद काफी बिगड़ गए थे। वर्ष 2024 में ब्रिक्स समिट व 2025 में एससीओ समिट के दौरान प्र.मंत्री मोदी व चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की वार्ता के बाद हालात सामान्य होने शुरू हुए थे।

■ शंघाई के भारतीय महावाणिज्य दूतावास के काउन्सिलेट जनरल प्रतीक माथुर ने प्रतिनिधिमंडल की चीन की प्रमुख कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ मीटिंग करवाई।

के दौरे पर है, जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल हैं। 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य गतिरोध के बाद पाँच वर्षों से अधिक समय तक चले ठहराव के उपरांत,

पिछले वर्ष दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध सामान्य होने के बाद, यह चीन जाने वाला पहला भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिण्डर पेस भाजपा में शामिल

नई दिल्ली, 31 मार्च। भारत के पूर्व टेनिस स्टार लिण्डर पेस मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू,

■ केंद्रीय मंत्री, भाजपा नेता सुकांता मजूमदार ने बताया कि पेस 19 वीं सदी के बांग्ला कवि व लेखक माइकल मधुसूदन दत्त के वंशज हैं।

सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में लिण्डर पेस ने भाजपा की सदस्यता ली। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भाजपा ने लिण्डर पेस को पार्टी में शामिल कराकर तुणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिण्डर पेस का स्वागत करते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीजू का अपमान “उडिया गौरव” का मुद्दा बन रहा है ओडिशा में

बीजू पटनायक पर भाजपा नेता निशिकांत दुबे की अपमानजनक टिप्पणी ने भाजपा को अटपटी स्थिति में डाला

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 मार्च। तटीय राज्य ओडिशा में उडिया गौरव को बहाल करने के मुद्दे पर सत्ता में आई पार्टी के लिए, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दिवंगत बीजू पटनायक के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए, पार्टी की राज्य इकाई को असहज स्थिति में डाल दिया है। बीजू पटनायक एक राजनीतिक महानायक और उडिया गौरव के प्रतीक माने जाते हैं।

दुबे ने हाल ही में आरोप लगाया कि 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान, बीजू पटनायक ने अमेरिकी सरकार, सीआईए और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया था। यह बयान राज्यभर में व्यापक आक्रोश का कारण बना हुआ है, और उनकी पार्टी के भीतर और बाहर, दोनों जगह दुबे की

■ निशिकांत दुबे ने 27 मार्च को लोकसभा के बाहर कहा था कि 1962 के युद्ध में बीजू पटनायक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू तथा अमेरिका व सीआईए के बीच कड़ी का काम किया था। दुबे के इस बयान पर भारी बवाल खड़ा हो गया।

■ बीजू पटनायक को ओडिशा में राजनैतिक महानायक व उडिया गौरव का प्रतीक माना जाता है। बीजू जन्मा दल ने इस बयान पर भारी नाराज़गी व्यक्त की तथा आमतौर पर शांत रहने वाले नवीन पटनायक ने इस पर भारी गुस्सा जताया, यही नहीं ओडिशा की भाजपा सरकार ने भी दुबे के बयान को उनका निजी विचार बताया और उनके बयान की कड़ी आलोचना की।

■ राजनैतिक विश्लेषकों का कहना है कि दुबे की टिप्पणी ओडिशा में “अंजैया इफैक्ट” ला सकती है। ज्ञातव्य है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टी. अंजैया का अपमान कर दिया था और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में एनटी रामाराव ने इस अपमान को “तेलगु प्राइड” का मुद्दा बनाकर भारी जीत प्राप्त की थी।

कड़ी आलोचना हो रही है। गत 27 मार्च को लोकसभा के बाहर दुबे ने कहा था कि नेहरू ने 1962 का युद्ध अमेरिका के पैसे और सीआईए के सहयोग से लड़ा

था। उन्होंने कहा, ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिका सरकार, सीआईए और नेहरू के बीच की कड़ी थे।

मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दुबे की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वकीलों को हटाना जेडीए अफसरों की मनमानी थी या राजनैतिक द्वेष?

जेडीए से हटाए गए सहायक अधिवक्ताओं को पुनर्स्थापित किया हाईकोर्ट ने

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 31 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा सहायक अधिवक्ता के पद पर नियुक्त कई वकीलों को बिना किसी कारण मनमाने तरीके से हटाये जाने के खिलाफ दायर 19 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें पूर्ववत पदों पर वापस लगाने तथा जेडीए को अधिवक्ताओं की नियुक्ति व हटाने के लिए गाइडलाइन बनाने के आदेश दिए हैं। इस गाइडलाइन में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सहायक अधिवक्ता और पैनल एडवोकेट की नियुक्ति में महिला, एससी-एसटी वर्ग की भागीदारी भी हो।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट

अपने कई आदेशों में दोहरा चुका है कि अधिवक्ता न्यायिक प्रणाली में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, उनके कारण ही न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहता है। हाईकोर्ट ने इसी टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि एक वकील को नौकर की भाँति नहीं समझा जा सकता, उन्हें पद से हटाने अथवा लगाने के लिए कोई ठोस वजह व कारण होना चाहिए।

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने अपने आदेश में जेडीए को निर्देश दिए हैं कि अधिवक्ताओं की नियुक्ति व हटाने के लिए विस्तृत पॉलिसी व गाइडलाइन बनाएँ।

इन 19 याचिकाओं में से अधिकतर वर्ष 2025 में दायर की गई हैं, जिनमें से याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2009 से 2014 के बीच नियुक्त किया

■ 19 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा “एक वकील को नौकर की भाँति नहीं समझा जा सकता, उन्हें पद से हटाने अथवा लगाने के लिए ठोस वजह व कारण होना चाहिए।”

■ वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने अदालत को बताया कि “वर्ष 2014 में जेडीए ने आदेश निकाला था कि अधिवक्ता को तब ही हटाया जा सकता है, जब जोनल कमिश्नर उनके काम से नाखुश हो, पर उनके मुवक्किल प्रताप सिंह के काम से जोनल कमिश्नर खुश थे, फिर भी उन्हें हटाया गया।”

■ वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर ने भी कहा कि, उनके मुवक्किल राम सिंह के पास वर्ष 2012 में जेडीए द्वारा जारी संतोषप्रद कार्य का अनुभव पत्र है, परंतु पिछली कांग्रेस सरकार में राम सिंह को तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आदेश पर हटाया गया था।”

गया था। इन याचिकाओं में कुछ याचिकाएँ वर्ष 2021 में भी दायर की गई थीं, जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा और कांग्रेस सरकार, दोनों ने जेडीए में नियुक्त सहायक अधिवक्ताओं को मनमाने ढंग से हटाया। यह सर्वविदित है कि जेडीए में लगे कई पैनल अधिवक्ताओं को भी कांग्रेस व भाजपा सरकार ने अपनी सरकार बदलने के साथ ही हटाया है। अधिवक्ताओं की नियुक्ति और हटाने के तरीके से स्पष्ट होता है कि राजनैतिक रसूख और सत्ताधारी पार्टी के जजदारी वकीलों को ही नियुक्तियाँ मिलती रही हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान मुख्य तौर पर 2 याचिकाओं को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया। इनमें पहली याचिका प्रताप सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिन्हें वर्ष 2009 में सहायक

अधिवक्ता के तौर पर नियुक्ति दी गई थी। इनका कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया था कि उन्हें पैनल एडवोकेट्स और जेडीए के अधिकारियों के बीच सेतु का काम करना था। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और उनके सहायक अधिवक्ता योगेश कल्ला पैरवी के लिए पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि सहायक अधिवक्ताओं को पद से हटाने की कोई तिथि तय नहीं की गई थी, लेकिन यह जरूर कहा गया था कि अगर उनके कार्य से जेडीए असंतुष्ट रहता है तो उन्हें बिना नोटिस हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जेडीए ने एक आदेश निकाला था कि अगर जोनल कमिश्नर (उपायुक्त) आपके कार्य से खुश नहीं है तो उन्हें हटाया जा सकता है। इसके बावजूद 14 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नालंदा : शीतला मंदिर में भगदड़, 9 की मौत

पटना, 31 मार्च। बिहार में नालंदा जिले के शीतला माता मंदिर में भगदड़ में 9 लोगों की अबतक मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। नालंदा के

■ नालंदा के पुलिस अधीक्षक ने बताया गम्भी और भीड़ के कारण हादसा हुआ। इसमें 9 की मौत हुई है तथा सात अन्य घायल हुए हैं। प्रमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए व घायलों को 50,000 रु. की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने बताया कि गम्भी और भीड़ की वजह से घटना हुई है। हादसे की जांच के लिए गठित एसआईटी ने छानबीन शुरू कर दी है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)